बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 181 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 18 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

लगता है हाईकोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल... दर्शन पुगुदीप मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली । कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता और हत्या का आरोप झेल रहे दर्शन पुगुदीप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से उन्हें मिली जमानत पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन मामले में ये सुनवाई कर्नाटक सरकार की याचिका के आधार पर की है. कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने टिप्पणी की कि लगता है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उचित विवेक का इस्तेमाल नहीं किया.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल; ईडी की चार्जशीट में कई और नाम

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसमें कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। मामला सितंबर 2018 का है, जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। वाड्रा पर आरोप हैं कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया। आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में

बेच दी। आगे चलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियमितताएं की गईं। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इस मामले में हुई कथित गड़बड़ी का खुलासा आईएएस अशोक खेमका ने किया था। इसके बाद वे सुर्खियों में आ गए थे। बीते एक दशक से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों ने अलग-अलग चुनावों में कांग्रेस पर आरोप साधने के लिए किया है। दिसंबर 2023 में ईडी ने इस मामले में यूएई स्थित व्यवसायी सीसी थंपी और ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी भूमि खरीद-बिक्री का विवरण शामिल है। ईडी ने कहा था कि वाड्रा से कथित तौर पर जुड़े थंपी ने 2005 से 2008 के बीच दिल्ली-एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के जरिए हरियाणा के फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोपपत्र के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 में एचएल पाहवा से अमीरपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े खरीदे और दिसंबर 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया। ईडी के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 40 कनाल (05 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया।

बीजेपी ने लगाया कोचिंग घोटाले का आरोप, आप बोली- स्कूलों की हर ईंट, मोहल्ला क्लीनिकों की हर सुई की जांच करें

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री अशीष सूद और सामाजिक कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने दिल्ली सचिवालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर दिल्ली में दलित, पिछले और अल्पसंख्यक बच्चों को आईएएस की मुफ्त कोचिंग करवाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली में सार्वजनिक सेवाओं के 'कार्यशील मॉडल को बंद कर दिया है' और उन्होंने पार्टी पर प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया. पार्टी ने बयान में कहा, ''दिल्ली के स्कूलों की हर ईंट, मोहल्ला क्लीनिकों की हर सुई की जांच करें... लेकिन जब आप अपना काम पूरा कर लें, तो कुछ वास्तविक काम करना शुरू करें.'' बीजेपी सरकार के मुताबिक, यह घोटाला कोरोना काल के दौरान जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में हुआ, जिसमें दलित, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितताएं की गईं. शिक्षा मंत्री अशीष सूद जानकारी दी की रेखा गुप्ता की सिफारिश पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए है और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार के मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शासन करने के दौरान एक ओर तो भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को दिखा-दिखाकर राजनीति की. दूसरी ओर उन्हीं के नाम पर शुरू हुई योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और योजना के तहत यूपीएससी, एसएससी, डीएसएसएसबी, नीट और क्लैट जैसी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए छात्रों को सरकारी सहायता दी जानी थी, लेकिन इसका लाभ लेने वाले हजारों छात्रों के नाम या तो फर्जी निकले या उनके दस्तावेज ही नहीं मिले.

यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे उपराष्ट्रपति, एलजी वीके सक्सेना संग किया दौरा

नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में यमुना वाटिका और बांसड्रा पार्क का दौरा किया, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनका स्वागत किया। धनखड़ ने भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि और राजधानी में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रयासों की भी सराहना की और दिल्ली में उनके काम को क्रांतिकारी बताया और कहा कि रिवरफ्रंट एक प्रमुख वैश्विक आकर्षण बनेगा। पत्रकारों से बात करते हुए, धनखड़ ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा किया गया कार्य क्रांतिकारी है। दिल्ली के लोग हमेशा याद रखेंगे कि उनके प्रयास फल दे रहे हैं। दिल्ली को नए फेफड़े, नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती थी। मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्लीवासी इस प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के अनुकूल सुंदरता का आनंद लेंगे, और यह अद्भुत होने वाला है। मुझे यकीन है कि रिवरफ्रंट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिवरफ्रंट से मेल खाएगा। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद यह एक वैश्विक आकर्षण होगा। धनखड़ ने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है, दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विकास तेज़ रहा है, बेहतर सड़कें, बिजली, गैस, शौचालय, इंटरनेट, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ हर घर तक पहुँच रही हैं। धनखड़ ने कहा कि कुछ अद्भुत हुआ है। मानवता के 1/6 हिस्से वाले भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक उछाल का अनुभव किया है। 11वें नंबर पर होने और दुनिया की पाँच सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने से लेकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चौथी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने तक। बुनियादी ढाँचे का विकास अभूतपूर्व और अकल्पनीय रहा है।

दिल्ली के मंत्रियों को महंगे फोन वाले आदेश पर सरकार की सफाई, कहा- ये चलता फिरता ऑफिस

नई दिल्ली ।

दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए लाखों के मोबाइल फोन वाले आदेश पर दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई दी गई है. मंत्री आशीष सूद ने इसको लेकर गुरुवार (17 जुलाई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. मंत्री आशीष सूद ने कहा, +आम आदमी पार्टी ने खुद ही कहा है कि उनके नेता बेरोजगार हैं, इनको काम चाहिए इसीलिए रोज आरोप लगाते रहते हैं कभी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कभी उनके परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं. आज आम आदमी पार्टी की टिप्पणी का जवाब देने के लिए बाध्य नही हैं क्योंकि वह व्यक्तिगत नहीं हैं वह ईमानदारी से काम करती हुई सरकार पर है. उन्होंने कहा, हमें काम करना है इसलिए हमने कभी जवाब नहीं दिया लेकिन दो दिन पहले दी गई टिप्पणी हमारी सरकार के ऊपर थी. सरकार के मंत्री फोन को लेकर बहुत यादा पैसे खर्च रहे हैं या आरोप लगाया गया. यह सरकार पर आरोप है इसके लिए जवाब देना जरूरी है. दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ये भी कहा, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मोबाइल फोन पर सरकार का काम करते हैं जनता का काम करते हैं. हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है मगर इनकी असलियत खोलने के लिए इस मोबाइल के विषय पर बात करनी जरूरी है. आम आदमी पार्टी के नेता ही अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छोड़ देते हैं ताकि हम उनकी सचाई सामने लेकर आएं. आशीष सूद ने आगे कहा, +साल 2013 का सर्कुलर था उसमें बढ़ोतरी करके डेढ़ लाख किया गया है. 2013 से 2025 आते आते बदलाव किया गया है सीपीआई के आधार पर जो बदलना चाहिए था वह बढ़ा दिया गया. सिर्फ हमारे एक ही मंत्री में पैसा क्लेम किया है बाकी तो किसी ने किया भी नहीं. मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के बेरोजगार नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को निभाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाकर लेकर आते हैं. मोबाइल एक जरूरत है. जनप्रतिनिधि के लिए मोबाइल एक चलता फिरता ऑफिस है. पहला फोन उन्होंने 81000 का लिया जबकि लिमिट सिर्फ 50000 रुपये की थी. दूसरा फोन 1,63,000 का फोन लिया जबकि अनुमति थी 50000 की थी. उन्होंने दावा किया, चार बार नया मोबाइल अरविंद केजरीवाल ने लिया जबकि अनुमति की राशि से दुगनी तिगुनी राशि वाला. विकसित होकर भ्रष्टाचार से आप यहां से गए हैं. कहते थे आम आदमी है छोटी शर्ट पहनेगी लेकिन कोविड के दौरान भी आईफोन खरीदेंगे. अरविंद केजरीवाल बड़े शौकीन मिजाज आदमी हैं.

प्यार का जाल बिछाया... लेकिन खुद ही फंस गई महिला, सुप्रीम कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली । शादीशुदा होते हुए दूसरे मर्द से रिश्ता रखने पर आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, पार्टनर पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है. महिला आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके सभी तर्कों को नकारते हुए जमानत को सही बताया है. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए महिला को खूब फटकार लगाई. महिला का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब महिला ने पति से तलाक ले लिया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपके दो बच्चे हैं. आप एक मैयोर महिला हैं और आपको उस रिश्ते की समझ थी जो आप शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ बना रही थीं. महिला के वकील ने फिर से दलील दी कि आरोपी याचिकाकर्ता को बार-बार होटल बुलाता था.इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कहा, आप उसके बुलाने पर बार-बार जाती क्यों थीं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शादीशुदा होते हुए किसी और से शारीरिक संबंध बनाना एक अपराध है. महिला ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने पाया कि महिला का तलाक होने के बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए. साल 2016 में सोशल मीडिया के जरिए महिला की आरोपी से जान-पहचान हुई. महिला का आरोप है कि आरोपी के दबाव में आकर उसने इस साल 6 मार्च को पति से तलाक ले लिया था, लेकिन जब उसने आरोपी से शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया. इस बात से महिला को बहुत गुस्सा आया और उसने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी कि आरोपी ने उसका रेप किया है. हालांकि, पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी क्योंकि कोर्ट ने पाया कि तलाक के बाद कभी आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए.

शिक्षा : दो विरोधी परिप्रेक्ष्य कम्युनिस्ट और आरएसएस

प्रभात पटनायक

भारत में कम्युनिस्ट अपने कार्य क्षेत्रों में स्कूल और कालेज स्थापित करने के लिए अक्सर सार्वजनिक चंदे करते और सार्वजनिक प्रयास करते आए हैं। बेशक, यह आरएसएस जैसे फासिस्ट संगठनों द्वारा बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए जाने की गतिविधि से पूरी तरह से अलग था। अव्वल तो कम्युनिस्टों ने शिक्षा संस्थाएं इसलिए स्थापित नहीं की थीं कि उन्हें नियंत्रित करें और उनके जरिए सिर्फ अपनी खास विश्व दृष्टि का प्रसार करें। उनका मकसद तो जनता के बीच शिक्षा के आम स्तर को ऊपर उठाना था और यह वे इस पक्के यकीन के साथ करते थे कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो वे खुद ही कम्युनिस्ट विश्वदृष्टि की कीमत समझ जाएंगे। इस तरह, कम्युनिस्टों द्वारा खड़ी की गयी संस्थाएं प्रामाणिक शिक्षा संस्थाएं ही थीं, न कि सिर्फ एक खास प्रचार करने का साधन। दूसरे, इसी कारण से कम्युनिस्टों ने सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाए थे, जैसे कि फासीवादी बनाते हैं, ताकि उन्हें आसानी से प्रभावित होने वाली उम्र से ही पकड़ा जा सके, बल्कि उन्होंने परिपक्व छात्रों के लिए कॉलेज भी बनाए थे, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक विचारों पर चर्चा कर सकें और राय बना सकें। दूसरे शब्दों में ये दो अलग-अलग उद्यम, शिक्षा के प्रति पूरी तरह से एक-दूसरे की विरोधी दृष्टियों को अभिव्यक्त करते थे। बर्टोल्ट ब्रेख्त ने जब लिखा था ''भूखे इंसान, किताब उठा'' वह शिक्षा के प्रति वामपंथ के रुख को ही अभिव्यक्त कर रहे थे, जो शिक्षा को ऐसी चीज मानता है जो नजरिए को विस्तृत करती है और इसलिए सारत: मुक्तिदायी होती है। शिक्षा के प्रति फासीवादी रुख इससे ठीक उल्टा होता है। इसके हिसाब से जनता के परिप्रेक्ष्य का किसी भी प्रकार से विस्तार होना, सारत: भीतरघाती होता है और इसलिए उसे कुचला जाना चाहिए। इसलिए, तमाम प्रामाणिक शिक्षा को कुचला जाना चाहिए और उसकी जगह पर फासीवादी प्रचार को बैठा दिया जाना चाहिए। जहां वामपंथ ''भूखे इंसान'' का आह्वान करता है कि ''किताब उठा'', फासीवादी किताबों को जलाने को बढ़ावा देते हैं, जैसा उन्होंने नाजी जर्मनी में किया था। आज के नव-फासीवादी, इस मामले में अपने पूर्ववर्तियों का ही अनुकरण करते हैं। वे शुद्ध रूप से आम तौर पर बौद्धिक गतिविधियों और एक सामाजिक समूह के रूप में बुद्धिजीवियों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तमाम उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऐसे ही निजाम वाले अन्य देशों में भी और यहां तक कि अमरीका में भी जिस तरह का ध्वंस हो रहा है, इसी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। भारत में अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की हिम्मत करने वाले बुद्धिजीवियों को प्रवर्तन निदेशालय के छापों से आतंकित किया जाना; उन पर ''खान मार्केट गैंग'' (उसका मतलब चाहे जो भी हो), ''टुकड़े-टुकड़े गैंग'', ''अर्बन नक्सल'' जैसे ठप्पे लगाकर उनके प्रति सार्वजनिक शत्रुता भड़काया जाना, आदि सभी इसी प्रवृत्ति के हिस्से हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अमरीका में डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि अमरीकी यूनिवर्सिटियां कम्युनिस्टों से भरी हुई हैं, जिन्हें चुन-चुनकर निकाले जाने की जरूरत है। इस तरह का भय, शिक्षा के प्रति नव-फासीवादी रुख में अंतर्निहित है। मोदी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को नष्ट करने की, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को ठप्प करने की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भीतर से खत्म करने की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को आतंकित करने की, दिल्ली विश्वविद्यालय को अस्थिर करने की, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को हथियाने की (जिसके खिलाफ छात्रों ने लंबा आंदोलन चलाया था) और बड़ौदा के महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग को नियंत्रित करने की, व्यवस्थित तरीके से कोशिशें की हैं। ये सभी ऐसी संस्थाएं हैं जो मुख्यत: आजादी के बाद बनी हैं, जिन पर देश सचमुच गर्व कर सकता है और इन संस्थाओं पर हमला देश के मौलिक और रचनात्मक चिंतन को बुझाने की सबसे भोंडी कोशिश का प्रतिनिधित्व करता है। विचार पर यह हमला उसी तरीके से कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर और अमरीका में अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं पर, ट्रम्प प्रशासन के हमले जैसा ही है। बहरहाल, सोच को बौना करने और बौद्धिक गतिविधि को कुचलने की नव-फासीवादी कोशिशों को समझना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक इससे काफी भिन्न चीज है, जो पहेली जैसी लगती है। क्या वजह है कि एक ऐसे देश में जहां हमेशा से बुद्धिजीवियों का बहुत सम्मान किया जाता रहा है (जो कि बेशक एक पूर्व-पूंजीवादी विरासत है) इस तरह की कोशिश को एक हद तक सफलता मिल गयी है? पढ़ने-पढ़ाने की दुनिया से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात की गवाही देगा कि अभी कुछ अर्सा पहले तक भारत में आम लोग बुद्धिजीवियों को, खासतौर पर शिक्षकों को, बड़े सम्मान की नजर से देखते थे। तब क्या वजह है कि बुद्धिजीवियों पर मोदी सरकार के हमले के प्रति वैसी हिकारत पैदा नहीं हुई है, जिसकी सामान्य रूप से उम्मीद की जाती थी। अमरीका का मामला इस लिहाज से थोड़ा अलग है। चूंकि उनका कोई सामंती अतीत नहीं है; वहां कभी भी बुद्धिजीवियों को वैसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठाया जाता था, जैसे भारत जैसे पुराने समाजों में सामान्य रूप से बैठाया जाता था। लेकिन, भारत में ठीक-ठीक ऐसा क्या हुआ है जिसने इसे बदल दिया है। इस तरह के बदलाव के पीछे काम कर रहा सबसे निर्णायक कारक, बेशक देश में नव-उदारवादी निजाम का आना ही रहा है। नव-उदारवाद ने इस बदलाव में कम से कम तीन अलग-अलग तरीकों से योग दिया है। पहला- इसने आय की असमानताओं को बहुत बढ़ा दिया है और हालांकि बुद्धिजीवी तथा शिक्षक ऊंची आय अर्जित करने वालों में नहीं रहे हैं, उनका एक उल्लेखनीय हिस्सा नव-उदारवाद के दौर में आम मेहनतकश जनता के मुकाबले में काफी खुशहाल रहा है। 1974 में जब भारत में एक क्विंटल गेहूं का सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपये था, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ऐसोसिएट प्रोफेसर का शुरुआती वेतन 1,200 रुपये प्रति माह होता था। आज गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये है, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ऐसोसिएट प्रोफेसर का शुरुआती बुनियादी मासिक वेतन, 1,31,400 रुपये है। बहुत ही मोटे तौर पर अगर इन आंकड़ों को इन दो श्रेणियों की आय की गति का संकेतक माना जाए तो, हम यह देखते हैं कि इस दौरान शिक्षक या अकादमिक की आय 100 गुना से ज्यादा बढ़ी है, जबकि किसान की आय 27 गुनी ही बढ़ी है। यानी इन वर्गों की आय का अनुपात, इस दौरान तीन गुना ज्यादा बढ़ गया है और यह दौर मोटे तौर पर नव-उदारवाद का दौर रहा है। ऐसे हालात में, अकादमिकों तथा अन्य बुद्धिजीवियों और मेहनतकशों के बीच अलगाव बढ़ जाने में शायद ही किसी को हैरानी होनी चाहिए। दूसरा कारण- पूंजीवाद पहले के समुदायों को तिरोहित करने का काम करता है। भारत में बुद्धिजीवियों का जो सम्मान हुआ करता था, वह पूर्व-पूंजीवादी दौर के समाज की भावना का ही विरासत थी। नव-उदारवादी निजाम ने देश में पूरे कद में और बिना किसी रू-रियायत के, पूंजीवाद को उन्मुक्त किया है। उसने पूर्व-पूंजीवादी दौर में रही समुदाय की भावना को विलीन करने का काम किया है। तीसरे, व्यक्तिकरण की इस प्रवृत्ति के साथ ही साथ, वैश्वीकरण की भी परिघटना चलती रही है, जिसका अर्थ था बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से का घरेलू समाज में अपनी जड़ों से कट जाना और उनके बीच वैश्विक मैटकेफिंग की प्रवृत्ति पैदा होना। पुन इसने भी उन्हें देश के मेहनतकशों से दूर किया है। इन सभी कारणों से नव-उदारवाद ने मेहनतकश जनता और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच खाई को चौड़ा करने में योग दिया है।

न्याय, जवाबदेही और मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है

वैश्विक स्तरपर एक दो दशक से जिस तरह संगठित अपराधोंकी संख्या में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व स्थानीय समूह की गतिविधियों में वृद्धि हुई है इसे गंभीरता से रेखांकित करना समय की मांग है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि उनके संगठित अपराधों को अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में देखें तो जांचएजेंसियों द्वारा आजकल अपराध की थ्योरी को अन्तर्राष्ट्रीय एंगल से जांच करने की थ्योरी भी अपनाई जाती है जिस तरह से वर्तमान में रूस- यूक्रेन इजराइल हमास युद्ध,व अनेक देशों के स्थानीय लोकल स्तरपर मानवीय अधिकार हनन अपराध चर्चा में आ रहा है व विशेष रूप से युद्ध अपराध चर्चा में आया है, युद्ध अपराध के लिए विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मानक मौजूद हैं, सहित अनेक केसों की तारें विदेशों तक जुड़ी हुई हैं। एक अपराधिक संगठन को हम गिरोह,माफिया, भीड़, सिंडीकेट, अंडरवर्ल्ड या गैंग्लैंड भी कह सकते हैं, जिसमें अनेक अपराध जैसे सफेदपोश अपराध, वित्तीय अपराध, राजनीतिक अपराध, युद्ध के अपराध सहित अनेक परिभाषित अपराधों को शामिल किया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय कनेक्टेड होते हैं इसीलिए आज हम ऐसे अपराधों और न्याय पर चर्चा करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में आते हैं उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने, दुनियाँ भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से सचेत रहने के प्रति जागरूक करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2025 के उपलक्ष में इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथियों बात अगर हम आज की दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 की प्रासंगिकता की करें तो (1) राजनीतिक संघर्षों, युद्ध अपराधों और असंख्य मानवाधिकार उल्लंघनों के इस युग में, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। (2)यह विश्वव्यापी स्तर पर एक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता की ओर ध्यानआकर्षित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार, बिना जवाबदेही के न बच सकें।(3) यूक्रेन, गाजा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उभर रहे संकटों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो आम नागरिकों की रक्षा करता है और आगे होने वाले अत्याचारों को प्रभावी रूप से रोक सकता है।(4) यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसी संस्थाओं और न्याय प्रशासन में राज्यों के बीच सहयोग के महत्व को भी उजागर करता है। (5) ऐसे युग में जहाँ बहुपक्षवाद और कानून के शासन को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह स्मरणोत्सव शांति, जवाबदेही और पीड़ितों के अधिकारों के प्रति वैश्विक निष्ठा की याद दिलाता है। (6) इसलिए यह एक ऐसी न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में प्रेरणा देता है जहाँ न्याय सीमाओं और राजनीतिक हितों से परे जाकरसख्ती से लागू हो। साथियों बात अगर हम विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने के उद्देश्यों की करें तो, (1) विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना तथा दुनिया में सबसे गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना है (2) यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे कानूनी तंत्रों के माध्यम से नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के कुख्यात अपराधियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। (3) यह दिवस मानवाधिकारों की सुरक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।(4) इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग और ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के माध्यम से एक अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष विश्व के निर्माण हेतु मिलकर काम करने की याद दिलाता है। साथियों बात अगर हमअंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को समझने की करें तो-परिचय (1) यह विश्व का पहला स्थायी, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जिन्होंने अत्यंत गंभीर अपराध किए हों। (2) इसमें चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को सम्मिलित किया गया है-नरसंहार, युद्ध संबंधी अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथाआक्रामकता से संबधित अपराध। (3) इस न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है और यह जुलाई 2002 से कार्य कर रहा है। (4) भारत ने अभी तक रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अतः वह आईसीसी का सदस्य नहीं है। (5) भारत का मानना है कि आईसीसी की कुछ धाराएं उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता, सैन्य कार्रवाई और आंतरिक सुरक्षा नीतियों के लिए बाधक हो सकती हैं। (6) भारत यह भी आशंका जताता हैकि आईसीसी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के वीटोयुक्त देशों का अत्यधिक प्रभाव है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ढांचे की करें तो,संयुक्त राष्ट्र सेसंबंधित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। इस न्यायालय में 6 भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज) में सुनवाई होती है, लेकिन काम अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 123 है। 17 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, इसने 1 जुलाई 2002 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

साथियों बात अगर हम न्यायालय की जरूरत की करें तो अपराध की दुनिया पर लगाम लगाने के लिए न्यायालय की जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व में न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी।प्रतिवर्ष आज ही के दिन 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के प्रति जागरूक करना है। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के क्रियाकल्प की करें तो, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक स्थाई और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ऑर्गनाइजेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन के आरोपियों को दंडित करने में सक्षम है। जिसमें नरसंहार का अपराध, अपराधों का युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल है। अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय स्थापना तब हुई जब, राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया इस की प्रतिमा को अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय के संविधि के रूप में जाना जाता है। आईसीसी राष्ट्रीय अदालतों की जगह नहीं लेता है। लेकिन यह तब उपलब्ध होता है जब कोई देश जांच करने में सक्षम नहीं होता और अपराधियों पर यह मुकदमा चला सकता है। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अंतिम उपाय मानने की करें तो, अंतिम उपाय की अदालत के रूप में सेवा करने के इरादे से,आईसीसी मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिकप्रणालियों का पूरक है और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालतें अनिच्छुक हों या अपराधियों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ हों। इसमें सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है और यह केवल सदस्य राज्यों के भीतर किए गए अपराधों, सदस्य राज्यों के नागरिकों द्वारा किए गएअपराधों, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा न्यायालय को संदर्भित स्थितियों में अपराधों की जांच और मुकदमा चला सकता है । अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2025- न्याय जवाबदेही और मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक हैदुनियाँ की सरकारें प्रण करें- अन्याय के नए रूपों को विफल करेंगे, न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे । वपीड़ितों को सशक्त बनाएंगे।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपराधियों के प्रत्यर्पण, आतंकवाद पनाहगार देशों का संज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने की शक्तियां देना समय की मांग है।

सम्पादकीय...

एक किताब उग्रवाद का..

किताब अल-तौहीद (एकेश्वरवाद की पुस्तक) वहाबी विचारधारा का एक मौलिक ग्रंथ है। इसे 18वीं शताब्दी में मुहम्मद इब्न अब्द अल-वहाब ने लिखा था। यह ग्रंथ तौहीद (इस्लामी एकेश्वरवाद) की कठोर एवं शाब्दिक व्याख्या पर जोर देता है। सलाफी हलकों में इसका आदर एक पुनरुत्थानवादी सिद्धांत के रूप में किया जाता है। इसकी वजह से ही इसका सीधा रिश्ता आईएसआईएस और अलकायदा जैसे हिंसक चरमपंथी समूहों के वैचारिक आधार से है। यह लेख इस बात की परख करता है कि आखिर किस तरह किताब अल-तौहीद को कट्टरपंथ, हिंसा और ऊपर वर्णित युवा मुस्लिम समूहों की भर्ती एवं उनके अनेक उप-समूहों को उचित ठहराने के लिए सहयोजित और हेरफेर किया गया है। मुहम्मद इब्न अब्द अल-वहाब का सिद्धांत व्यापक धार्मिक नवीन चलनों (बिदअ'ह) और शुद्ध इस्लामी एकेश्वरवाद से भटकाव के जवाब में उभरा। यह ओटोमन खिलाफत का युग था और सूफी संतों की पूजा तथा उनके मजारों या खानकाहों पर आज की तरह ही व्यापक रूप से सभाएं होती थीं। इसे इस्लाम के एक नरम एवं पारंपरिक रूप के तौर पर देखा गया। अब्द अल-वहाब ने ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने का आह्वान किया क्योंकि उनके अनुसार वे तौहीद (ईश्वर की एकात्मकता और उसके एकमात्र प्राधिकार की सर्वोच्चता) के सिद्धांत के उलट थीं। उनका सिद्धांत सूफियों के पास जाने को मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थता की चाह के रूप में देखता था। उन्होंने इसे शिर्क (बहुदेववाद या ईश्वर के समान प्राधिकार को स्वीकार करना) कहा। उनके विचार में धार्मिक स्थलों पर जाना झूठे देवताओं की चौखट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने या मूर्ति पूजा करने जैसा था। वहाब के विचारों को सबसे पहले अरब जनजातियों के बीच मान्यता मिली और जल्द ही उन्होंने एक जनजातीय सरदार मुहम्मद इब्न सऊद के साथ गठबंधन के जरिए राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सऊदी राज्य का निर्माण हुआ। इसके बाद ही वहाबी विचारधारा का संस्थागत स्वरूप सामने आया। किताब अल-तौहीद में मुसलमानों को सच्चे एकेश्वरवादी और विधर्मी में विभाजित करने वाले अडिग द्वैतवाद ने उन तकफीरी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की, जो मुसलमान बंधुओं को बहिष्कृत करती हैं। तकफीरियों का मानना है कि एक बार जब मुसलमान मूल इस्लामी सिद्धांतों से भटक जाते हैं तो वे दुश्मन बन जाते हैं और इस तरह उनका विनाश हो जाता है। किताब अल-तौहीद की सैद्धांतिक कठोरता इसकी एक बड़ी खामी है। शोध के अभाव में भी, यह एक ऐसा विमर्श पेश करता है जो एक लंबे फतवे या आदेश जैसा प्रतीत होता है। इसमें कई ऐसे अप्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ और गलत व्याख्याएं हैं जो शुद्ध तौहीद से भटकाव को अविश्वास के बड़े कृत्य के रूप में वर्गीकृत करती हैं, जिसकी सजा अक्सर मौत होती है। दुनिया को नजर में यही द्विआधारी दृष्टिकोण आईएसआईएस द्वारा जाने इस्तेमाल किए वाले तकफीरी तर्क का आधार रहा है। सरल शब्दों में, तकफीर किसी अन्य मुसलमान को धर्म का त्याग करने वाला (इस्लाम की परिधि से बाहर) घोषित करने और फिर उसे मौत की सजा देने का कार्य है। यह खतरनाक सिद्धांत आईएसआईएस की विचारधारा का केन्द्र बिन्दु है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक मुसलमानों, सूफियों, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों तथा आईएसआईएस का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति की हत्या को सही ठहराने के लिए किया गया है, गैर-मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आईएसआईएस द्वारा किताब अल-तौहीद का इस्तेमाल आईएसआईएस अपने प्रचार एवं प्रशिक्षण से जुड़े साहित्य में अक्सर अपनी हिंसा को वैध ठहराने के लिए किताब अल-तौहीद और अन्य वहाबी ग्रंथों का हवाला देता है। इस पुस्तक की व्याख्याएं भर्ती होने वाले लोगों के सामने इस बात के सबूत के रूप में पेश की जाती हैं कि धर्म का त्याग करने वालों और विधर्मियों की हत्या न केवल जायज है, बल्कि उम्माह की शुद्धि के लिए जरूरी भी है। आईएसआईएस द्वारा प्राचीन धार्मिक स्थलों का विनाश इस कट्टरपंथी वहाबी विचारों का नतीजा है कि ऐसे स्थान 'मूर्ति पूजा' के भौतिक प्रतीक हैं और इन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। इस मूर्तिभंजन को इस किताब में उद्धृत उन्हीं आयतों और पाठ के जरिए तर्क संगत बनाया गया है। किताब अल-तौहीद का खतरा उसके अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके हथियारीकरण में निहित है। हाल के वर्षों में डिजिटल सलाफीवाद के उभार ने भारतीय मुस्लिम युवाओं के कुछ वर्गों को गहराई से प्रभावित किया है। इन कंटेंट में किताब अल-तौहीद के सुलभ अनुवाद भी शामिल हैं। ये कंटेंट अक्सर इस्लाम की एक संकीर्ण और बहिष्कारकारी व्याख्या का समर्थन करते हैं, सूफी संतों की पूजा और दरगाहों की यात्रा जैसी पारंपरिक प्रथाओं को गैर-इस्लामी या यहां तक कि बहुदेववादी करार देते हैं। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में युवा मुसलमान भारत की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण इस्लामी विरासत से खुद को दूर कर रहे हैं। इसकी वजह से पहचान संबंधी भ्रम, बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन और अन्य मुस्लिम संप्रदायों के प्रति असहिष्णुता में वृद्धि हो रही है। बाहर से वित्त पोषित होने वाले नेटवर्क और विनियमन से रहित डिजिटल कंटेंट द्वारा प्रेरित विचारधारा में यह बदलाव हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। भारतीय मुस्लिम युवाओं पर कट्टरपंथी प्रभाव और भारतीय सूफी इस्लाम का इससे निपटने का तरीका हाल के वर्षों में भारतीय मुस्लिम युवाओं पर किताब अल-तौहीद का वैचारिक प्रभाव अनूदित साहित्य, ऑनलाइन प्रवचनों और विदेशी वित्त पोषित सलाफी संस्थाओं के जरिए तेजी से पड़ा है। भारतीय मुस्लिम युवाओं के एक वर्ग में, किताब अल-तौहीद ने देश की समृद्ध इस्लामी परंपराओं के प्रति बढ़ती अस्वीकृति को बढ़ावा दिया है। इसने उन्हें अपनी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जड़ों से दूर कर दिया है। इससे सांप्रदायिकता, पहचान संबंधी भ्रम और कुछ मामलों में ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट और अतिवादी नजरिए के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। इस्लाम को एक कठोर सिद्धांत तक सीमित कर देने से नैतिकता, करुणा और सांप्रदायिक सदभाव पर जोर भी कम हो गया है ।

कांवड़िये और क्यूआर कोड

भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबमें केवल हिन्दू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें विशाल विविधता समाई हुई है। एक तरफ जहां यह विश्व बंधुत्व को मानता है और समूची सृष्टि के कल्याण की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ अन्य धर्मों का भी बराबर सम्मान करता है। हिन्दुओं में सनातन धर्मावलम्बी साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो दूसरे निराकार ब्रह्म के उपासक भी पाये जाते हैं। इनमें भी अलग-अलग पूजा पद्धतियां होती है मगर सबमें एक सिद्धान्त सांझा है कि सभी भारत भूमि को पूजनीय मानते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हिन्दू धर्म के प्रतीक व देव स्थल केवल भारतीय उप महाद्वीप के भीतर ही हैं। लगभग यही स्थिति भारत में जन्म लेने वाले अन्य धर्मों जैसे सिख, बौद्ध, जैन आदि की भी है। अपनी जन्मभूमि भारत को ही इन सभी धर्मों के निवासी स्वर्ग के समान मानते हैं। विशेषकर हिन्दू धर्म तो कहता है कि हिन्दुओं के सभी तीर्थ और वेद-पुराणों से जुड़े पूजनीय स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ही हैं। हिन्दू धर्म में समय को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार साल के सभी 12 महीने कोई न कोई विशेष सन्देश देते हैं जिनका वर्णन हमें लोकोक्तियों में मिलता है और हर महीने में पड़ने वाले त्यौहारों से इसका पता चलता है। इनमें सावन के महीने की महत्ता अलग से व्याख्यायित है। हिन्दू धर्म प्रकृति के साथ किस प्रकार का सामंजस्य बैठाता है, इसका अन्दाज भी हमें सावन महीने में होने वाले उत्सवों से आसानी से होता है। सावन के महीने में तो भगवान शंकर की पूजा-अर्चना करना बहुत पुण्य कमाने का काम समझा जाता है। इस महीने में पड़ने वाले त्यौहारों का वर्षा से सीधा सम्बन्ध रहता है। इस दौरान हिन्दू मतावलम्बियों का न केवल पूजा-पाठ से विशेष तारतम्य रहता है बल्कि इसका असर उनके खान-पान व पहनावे पर भी रहता है। यहां तक कि उनके काम करने के तरीके पर भी । सावन मास पूरी तरह भगवान शंकर को समर्पित रहता है। शंकर या शिव समूचे ब्रह्मांड के संहारकर्ता माने गये हैं और प्रकृति के सन्तुलक भी कहे जाते हैं। प्रकृति को जल के रूप में लेने का सावन मास एक उदाहरण है। इस महीने में पड़ने वाले सारे सोमवार शंकर जी को ही समर्पित रहते हैं। इसमें वैज्ञानिकता का पुट यह है कि सावन मास मनुष्य को केवल सात्विक भोजन करने की व्यवस्था देता है। अतः इस महीने में तामसी भोजन जैसे मांस, मच्छी खाने की मनाही होती है। शाकाहारी लोगों के लिए प्रकृति अमृतफल आम जैसी वस्तुएं प्रदान करती है। सावन मास में पवित्र गंगाजल शिव जी को चढ़ाने की प्रथा हिन्दुओं में है।

वर्तमान समय में हिन्दू श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ भरते हैं और गंगाजल लेकर आते हैं। जिसे वह अपने-अपने स्थान के शिव मन्दिरों में चढ़ाते हैं। जाहिर है कि कांवड़िये कहे जाने वाले शिवभक्त अपनी यात्रा के मार्ग में पूर्ण रूप से सात्विक या शाकाहारी भोजन ही लेना पसन्द करेंगे। अतः मार्ग में यदि कोई मांस-मच्छी की दुकान पड़ती है तो उसे थोड़े समय के लिए स्वयं ही बन्द रहना चाहिए। यही पर भारत की मूल विश्व बन्धुत्व की संस्कृति को जागृत किया जाना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि इसके लोगों के बीच बंधुत्व बढ़ना सरकारों का लक्ष्य होना चाहिए। मगर बन्धुत्व केवल हिन्दुओं के त्यौहारों पर ही नहीं दिखना चाहिए, बल्कि अन्य धर्मावलम्बियों विशेषकर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान नागरिकों के बीच भी दिखना चाहिए। बेशक भारत एक धर्म या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हिन्दुओं के त्यौहारों को हम साम्प्रदायिक कहने लगें और मुसलमानों के त्यौहारों को धर्म निरपेक्ष। हिन्दू धर्म किसी भी स्तर पर संकीर्णता का परिचय नहीं देता है बल्कि वह दूसरे धर्मों के साथ सहयोग करके चलने की हिदायत देता है। इसके लिए इतना कहना ही काफी है कि जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो भारत ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जबकि भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या 80 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। इसका सीधा-साधा निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि हिन्दू स्वयं में ही धर्मनिरपेक्ष है। हिन्दू धर्म की धर्मनिरपेक्षता का असर इसके अनुयायियों पर न पड़े यह कैसे सम्भव है? सत्य तो यही रहेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है क्योंकि इसमें हिन्दुओं की बहुसंख्या है। मगर भारत संविधान से चलने वाला देश है और संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को अपनी आस्था और धर्म के अनुसार जीने का हक है। चूंकि भारत का समाज बहुधर्मी है अतः सभी लोगों को आपस में बंधुता या भाईचारा बढ़ाने के सद्प्रयास करने चाहिए। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले खाने-पीने के ढाबों के मालिकों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे डिजिटल भुगतान करने हेतु अपना क्यूआर कोड या चिन्ह दुकान के बाहर लगायें जिससे यात्रियों को उसके असली मालिक का पता लग सके। मगर कुछ लोग इसमें साम्प्रदायिकता ढूंढ रहे हैं और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनकी क्यूआर कोड के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब अगले मंगलवार तक दाखिल करने का आदेश दिया है। पिछले वर्ष भी योगी सरकार ने दुकान मालिक का नाम दुकान के बाहर टांगने का निर्देश दिया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया था। मगर इस बार मामला क्यूआर कोड का है। याचिका दायर करने वाले कह रहे हैं कि योगी सरकार ऐसा इसलिए कर रही है जिससे साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। यह कहना इसलिए गलत है क्योंकि योगी सरकार कानून के अनुसार केवल यही कह रही है कि क्यूआर कोड को दुकान पर दिखाया जाये जिससे उपभोक्ता बने कांवड़ियों द्वारा नाम जानने के अधिकार का पालन हो सके क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोई भी चीज बाजार से खरीदने वाले को यह हक देता है कि वह दुकान मालिक की पहचान करे।

स्टॉक मार्किट में खरीद-फरोख्त और शार्ट-सैलिंग

भारत में गत वर्षों में स्टॉक मार्किट विश्व स्तर पर काफी ऊपर चली गई है। इस समय यह वैश्विक स्तर पर हॉन्गकॉन्ग को पछाड़ कर पांचवें पायदान पर पहुंच गई है, जिस में लिस्टेड शेयर्स की वेल्यू अनुमानतः लगभग 5.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस समय भारत में लगभग 8.7 करोड़ आम निवेशक हर रोज शेयर मार्किट में खरीद-फरोख्त करते हैं जिसकी अनुमानित वेल्यू लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है। स्टॉक मार्किट में खरीद-फरोख्त के लिए निवेशक वैसे तो आमतौर पर नीति अपनाते हैं कि 'सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो' परन्तु कुछ ट्रेडर्स इसके उल्ट भी नीति अपनाते हैं जिसमें 'महंगे में बेचो और सस्ते में खरीदो'। इस नीति को शार्ट-सैलिंग भी कहते हैं। स्टॉक मार्किट में शार्ट-सैलिंग का मतलब है किसी ऐसे स्टॉक को बेचना जो आपके पास नहीं है यह मानकर कि उसकी कीमत गिर जायेगी। अगर कीमत गिरती है तो आप कम कीमत पर स्टॉक खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ नीतिकार बाजार में कुछ रिपोर्ट या अफवाहों के आधार पर मार्किट को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे ऐसे शेयर बेच देते हैं जो तब उनके पास नहीं होते और बाद में मार्किट के गिरने पर सस्ती कीमत में खरीद कर उसे पूरा कर लेते हैं। शार्ट-सैलिंग कुछ वर्ष पूर्व काफी खबरों में चर्चित रहा जब अमेरिका के एक शार्ट-सैलर एक अमेरिकन कम्पनी हिण्डनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें इस ग्रुप के विरुद्ध काफी आरोप लगाये गये थे, जिसके कारण अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी नीचे गिर गये थे (अनुमानतः लगभग 100 बिलियन डॉलर तक), और खबरों के मुताबिक इस अमेरिकन कम्पनी ने बाद में मुनाफा कमाया लेकिन इस सारे प्रकरण में भारतीय बाजार में काफी हलचल हुई और पूंजी निवेशकों का काफी नुकसान भी हुआ। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसी प्रकार की नीति के अन्तर्गत अभी हाल में एक और अमेरिकन शार्ट सैलर कम्पनी 'वाईसराय रिसर्च' ने भारत की एक विश्व विख्यात कम्पनी वेदांत ग्रुप के बारे में रिपोर्ट निकाली जिसमें आरोप लगाये गये कि इस कम्पनी के कार्यों में अनेक वित्तीय अनियमितताएं हैं। इसके फलस्वरूप इस कम्पनी के शेयर भी अचानक नीचे आ गये जिससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। उधर कम्पनी ने इस रिपोर्ट और उन आरोपों की गहरी भर्त्सना की, कि यह सारे आरोप निराधार और झूठे हैं और कम्पनी की सालाना वार्षिक बैठक से पहले दिन जानबूझ कर कम्पनी को नुकसान पहुंचाने के लिए निकाले गये हैं। ध्यान रखने योग्य है कि वेदांता ग्रुप धातु उद्योग और क्रिटिकल मिनरल्स जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं, एल्युमिनियम, लोहा, ऊर्जा और तेल व गैस के मामलों में दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके कई कार्य उत्पादन दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, लाईबेरिया, संयुक्त अरब अमिरात, साऊदी अरब, कोरिया, ताईवान और जापान में भी हैं और कई क्षेत्रों जैसे एल्युमिनियम आदि में वे वैश्विक स्तर पर पहले या दूसरे नम्बर पर माने जाते हैं। पिछले दिनों वेदांता ने डीमर्जर का प्लान बनाया था जिसके अनुसार चार स्वतंत्र इकाईयां बनाई जायेंगी जिसमें एल्युमिनियम, ऑयरन एण्ड स्टील, पॉवर तथा ऑयल एण्ड गैस से संबंधित इकाईयां होंगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पाँडवनगर एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

मान्यता प्राप्त पत्रकारों के संगठन ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर गहरी चिंता जताई

नई दिल्ली अजय कुमार चौधरी) मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ (रजि.) ने लोकप्रिय, निर्भीक और वरिष्ठ पत्रकार तथा मीडिया न्यूज चैनल के प्रधान संपादक श्री अजीत अंजुम के विरुद्ध बिहार में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) पर गहरा रोष और गंभीर चिंता व्यक्त की है।

संघ का स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जब इस स्तंभ को सच दिखाने की सजा दी जाती है, तब यह केवल एक पत्रकार पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ताने-बाने पर हमला माना जाता है।

सत्य और साहस की पत्रकारिता पर दमन का प्रयास निंदनीय है द्य

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री अजीत अंजुम ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा हो रही तमाम प्रशासनिक अनियमितताओं और खामियों को तथ्यपरक ढंग से उजागर किया। उन्होंने बिना किसी भय या दबाव के, जनता के हित में, प्रशासन की गंभीर गड़बड़ियों को अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाया। यही रिपोर्टिंग उनके ऊपर एफआईआर का कारण बनी, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत है।

संघ के अध्यक्ष विजय शंकर

चतुर्वेदी का स्पष्ट और सशक्त बयान

संघ के अध्यक्ष श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा-

अजीत अंजुम पत्रकारिता की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम है, जिनकी निष्पक्षता और ईमानदार रिपोर्टिंग को दशकों से देश भर में सराहा गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध सीधा हमला है। प्रशासन का यह कदम प्रेस की आज़ादी को दबाने और सच को छुपाने का घृणित प्रयास है।

उन्होंने कहा-

लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है 'सत्य का सम्मान'। अगर सच्चाई को उजागर करने वालों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाएगा तो यह समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत चिंताजनक संकेत है।÷

संघ ने प्रशासन से रखी तीन प्रमुख मांगे-

एफआईआर की तटस्थ और निष्पक्ष जांच कर निष्कलंक पत्रकार की गरिमा बहाल की जाए।

पत्रकारों को प्रताड़ित करने और दबाव में लेने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगे।

पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की पूर्ण रखा सुनिश्चित की जाए।

संघ का संकल्प – पत्रकारों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा

मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब भी किसी पत्रकार की स्वतंत्रता या गरिमा पर प्रहार होगा, पूरा पत्रकार समाज एकजुट होकर उसका डटकर मुकाबला करेगा।

हम अजीत अंजुम जैसे निर्भीक पत्रकारों के साथ खड़े हैं। हम हर उस पत्रकार के साथ हैं जो सत्य की राह पर डटकर खड़ा है। प्रेस की आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की रखा के लिए हम हर मंच पर संघर्षरत रहेंगे।÷

पत्रकारिता कोई अपराध नहीं – पत्रकारों का दमन बर्दाश्त नहीं!

लोकतंत्र का प्रहरी झुकेगा नहीं – सच बोलना बंद नहीं होग

राष्ट्र टाइम्स की 45वीं वर्षगांठ पर सरदार गुरुचरण सिंह राजू का भव्य सम्मान

नई दिल्ली द्य (इंद्रजीत सिंह) प्रतिष्ठित समाचार पत्र ÷राष्ट्र टाइम्स÷ ने अपनी स्थापना के 45 स्वर्णिम वर्षों के गौरवमयी अवसर पर समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सरदार गुरुचरण सिंह राजू को विशेष सम्मान से अलंकृत किया।

राष्ट्र टाइम्स के वरिष्ठ संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने स्वयं राजू जी को सम्मानित करते हुए उन्हें स्मारिका, शॉल एवं विशेष प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

इस अवसर पर श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा –

> ÷सरदार गुरुचरण सिंह राजू जी आज समाज के उन प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों में से हैं, जिनके निस्वार्थ सेवाभाव, अथक परिश्रम और जनहित के प्रति गहन समर्पण ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अद्वितीय कार्य किया है। उनके कार्यों में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण झलकता है।÷

उन्होंने कहा कि –

÷राष्ट्र टाइम्स की परंपरा सदैव रही है कि वह समाज के उन सच्चे सिपाहियों को सम्मानित करता है जो बिना किसी प्रचार-प्रसार की इच्छा के निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में समर्पित रहते हैं। राजू जी का जीवन स्वयं में एक आदर्श है – सेवा, संघर्ष और समाज के प्रति निष्ठा का

प्रतीक। हम उनके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सामाजिक योगदान की मंगलकामना करते हैं।÷

श्री चतुर्वेदी ने राजू जी के सामाजिक सरोकारों की खुले दिल से प्रशंसा की। उपस्थित लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि समाज को आज ऐसे ही कर्मठ, संवेदनशील और जनहितैषी व्यक्तित्वों की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस सम्मान का उद्देश्य केवल राजू जी के अथक प्रयासों का सम्मान करना ही नहीं था, बल्कि उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना था, जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में कहा –

> ÷हमारी शुभकामनाएँ सदैव आपके साथ हैं, राजू जी। समाज आपके समर्पण, ऊर्जा और संघर्ष की भावना से प्रेरणा लेता रहेगा। राष्ट्र टाइम्स आपके निरंतर सामाजिक प्रयासों पर गर्व करता है।÷

19 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 19 जुलाई को जिला जींद के जुलाना उपमंडल में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और नंदगढ़ में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी मुख्य रूप से शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर उनके पैतृक गांव नंदगढ़ में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी श्रीमती रेखा गुप्ता को हरियाणवी परंपरा के अनुरूप कोथली भी भेंट करेंगे।

उद्योग मंत्री राव नरबीर ने दिए एचएसआईआईडीसी को गठन उद्देश्य पर कार्य करने के निर्देश

गुरुग्राम में कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला 1 नवंबर को, ग्रीन बेल्ट व सोलर योजना पर भी विशेष फोकस

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम को अपने मूल उद्देश्यों पर केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध करवाना है और इसी लक्ष्य की दिशा में समर्पित प्रयास किए जाने चाहिए। श्री राव नरबीर सिंह ने यह निर्देश हाल ही में निगम अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा भूमि भागीदारी नीति–2022 के तहत किसानों व ग्रामीणों को जागरूक किया जाए कि एचएसआईआईडीसी उनकी दी गई आधी भूमि को विकसित कर भू-मालिकों को हिस्सेदार बनाएगा। इस प्रक्रिया में पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेते हुए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को निगम की कार्यप्रणाली की स्पष्ट समझ दी जा सके। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को बताया कि गुरुग्राम अब वैश्विक कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। इसके चलते सोहना, मानेसर और बावल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कन्वेंशन सेंटर का विकास किया जाए। इसके लिए नए गुरुग्राम के सेक्टर-65 में स्थित नगर निगम की भूमि को चिह्नित कर वहां आगामी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर इस कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मंत्री ने कहा कि एचएसआईआईडीसी को हर आईएमटी में उच्च गुणवत्ता और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों को उचित ठहराव सुविधा मिल सके। उन्होंने हरित हरियाणा अभियान के तहत निगम की सभी औद्योगिक सम्पदाओं में अधिकतम ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर बल दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इन ग्रीन बेल्ट के साथ बने फुटपाथों पर टाइल्स न लगाई जाएं, जिससे प्राकृतिक जल संचयन में कोई बाधा न आए। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 135 किलोमीटर लंबा कुंडली–मानेसर–पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे एचएसआईआईडीसी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपदा है। इसके संपूर्ण रख-रखाव व सौंदर्यकरण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केएमपी के दोनों और बड़े स्तर पर विशेष पौधारोपण अभियान चलाया जाए तथा हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सौर ऊर्जा चालित पंपों की स्थापना की जाए, जिससे बारिश के बाद पौधों की सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे के मानेसर से पलवल तक के हिस्से की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए।

दिल्ली में केवल इन महिलाओं को ही मिलेगा डीटीसी बसों में मुफ्त सफर : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी में डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर करने वाली दिल्ली की बाहर की महिलाओं को झटका लग सकता है. अब मुफ्त सफर केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए ही होगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (17 जुलाई) को कहा कि जल्दी ही दिल्ली की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास लाएंगी. ये पास दिल्ली की महिलाओं को ही दिए जाएंगे. दिल्ली की पूर्ववर्ती आप सरकार ने अक्तूबर 2019 को महिलाओं के लिए फ्री बस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत कोई भी महिला डीटीसी की बसों में फ्री में यात्रा कर सकती है. उन्हें बस में चढ़ने के बाद फ्री में पिंक टिकट लेना होता है. पिंक टिकट लेना अनिवार्य है. अब नए नियम के आने के बाद दिल्ली के बाहर की महिलाओं को सफर के लिए पैसे देने होंगे. नंदनगरी डिपो में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डीटीसी को 65000 करोड़ रुपये के घाटे से उबारेंगे. IIT की मदद से बस रूट्स को तैयार किया जा रहा है. पिछले दिनों दिल्ली के अधिकारी ने बताया था कि दिल्ली की महिलाओं को "सहेली स्मार्ट कार्ड" दिया जाएगा, जो पूरी तरह डिजिटल होगा. कार्ड पर नाम और तस्वीर होगी. अधिकारी ने बताया था कि स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी किया जाएगा. NCMC सिस्टम दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो में पहले से है. कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, पासपोर्ट फोटो और बैंक द्वारा मांगे गए अन्य केवाईसी दस्तावेज देने होंगे. आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं खत्म कर रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि आप सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार हुए हैं. इससे संस्था को काफी नुकसान हुआ है.

धमकाकर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

नई दिल्ली । एक व्यक्ति को बंदूक के दम पर डराकर उसे जमीन बेचने के लिए मजबूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं ललित मोहन राय और ललित राय की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने साल 2023 में 60 खाता जमीन को धोखाधड़ी से खरीदा और जमीन के मालिक को बंदूक के दम पर डराकर उसके हस्ताक्षर कराए गए। इस मामले में 26 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपियों ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और अग्रिम जमानत देने की अपील की। हालांकि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। चार साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक विवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक रूसी महिला का पता लगाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। महिला कथित तौर पर अपने चार साल के बच्चे को लेकर फरार हो गई है। यह बच्चा विवाहेतर संबंधों से पैदा हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बिना समय गंवाए लापता बच्चे का पता लगाने और उसकी कस्टडी प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को रूसी महिला का पासपोर्ट जब्त करने का भी निर्देश दिया है और एयरपोर्ट और माइग्रेशन अथॉरिटीज को देश भर के सभी एयरपोर्ट्स के प्रवेश और निकास पर नजर रखने का निर्देश दिया है।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हांसी के तहसीलदार पर की कार्रवाई

विवाह प्रमाण पत्र देरी से जारी करने पर लिया संज्ञान

चंडीगढ़ ।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में चार माह की अनावश्यक देरी के एक मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार पर 1 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवज़ा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह कार्रवाई सेवा के अधिकार अधिनियम की धारा 17(1)(a) के अंतर्गत की है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया यह मामला हिसार निवासी द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन देने के उपरांत शुरू हुआ था। विवाह 28 नवम्बर 2023 को संपन्न हुआ था और आवेदन माता-पिता की सहमति के साथ विलंबित विवाह पंजीकरण श्रेणी में किया गया था। दोनों वधू और वर हरियाणा के निवासी हैं और उनके पास वैध फैमिली आईडी मौजूद है, जिससे उनकी आयु एवं पता की पुष्टि होती है। उन्होंने बताया कि विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का हवाला देते हुए आपत्ति लगाई गई और प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, तहसील कार्यालय में भौतिक फाइल एवं अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार फैमिली आईडी से ही उम्र और पते का सत्यापन किया जाना था और पृथक से कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग के समक्ष 15 जुलाई को हुई सुनवाई में विवाह रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया कि उन्होंने विवाह क्लर्क के बयानों पर भरोसा किया और स्वयं निर्देशों की समीक्षा नहीं की। उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए खेद जताया और आश्वस्त किया कि विवाह प्रमाण पत्र उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के प्रवक्ता ने बताया आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि विवाह पंजीकरण जैसी सेवा, जिसके लिए 5 से 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित है, उसमें चार माह की देरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी समय पर निर्देशों का पालन करते तो विवाह प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो सकता था। आयोग ने उपायुक्त हिसार को निर्देश दिए हैं कि हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार के जुलाई माह के वेतन से कुल 6 हजार रुपये की कटौती सुनिश्चित करें, जिसमें 1 हजार रुपये की राशि राज्य कोष में जमा करवाई जाए तथा 5 हजार रुपये की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में अंतरित की जाए। इसके साथ ही आयोग ने सीआरआईडी को निर्देश दिया है कि विवाह रजिस्ट्रारों एवं संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-संवेदनशीलता सत्र का आयोजन शीघ्र किया जाए, जिससे राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की सही जानकारी फील्ड स्तर तक पहुंच सके।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किया महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

-कोरियावास में इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने के प्रयास में सरकार

चंडीगढ़ ।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में अरावली की वादियों के बीच बना महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है। कनेक्टिविटी, लोकेशन तथा वातावरण के हिसाब से यह हरियाणा का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की जाएं। यहां छात्रावास, अस्पताल विंग तथा शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री आज महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में स्थित मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां 700 सीटें थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2185 हो गई है और भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उज्ज्वल दृष्टि योजना÷ के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना हरियाणा में पहली बार लागू की गई है। इसमें पूरे राज्य में मुफ्त चश्मे वितरित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले मेडिकल कॉलेज भवन के शैक्षणिक ब्लॉक में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विंग तथा छात्रावास का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर नारनौल के विधायक श्री ओमप्रकाश यादव, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक श्री यशवेंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

इंफाल जाने वाला इंडिगो का विमान दिल्ली लौटा, बीच हवा में आई तकनीकी खराबी

नई दिल्ली ।इंफाल जा रहा एक इंडिगो विमान गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण एक घंटे तक हवा में रहने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, 17 जुलाई 2025 को दिल्ली से इंफाल जाने वाली उड़ान संख्या 6ई 5118 में उड़ान भरने के तुरंत बाद एक मामूली तकनीकी खराबी का पता चला। एहतियाती कदम के तौर पर पायलटों ने विमान को वापस मोड़ने का फैसला किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया। इंडिगो ने कहा कि अनिवार्य प्रक्रियाओं के अनुसार विमान की आवश्यक जांच की गई। इसके बाद तुरंत यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। उन्होंने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार 24.कॉम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ान संख्या 6ई 5118 को संचालित करने वाला ए321 विमान दिल्ली लौटने से पहले एक घंटे तक हवा में रहा।

मुस्लिम बहुल इलाके में बना मंदिर, पुजारी से बोले आप विधायक चौधरी जुबैर अहमद

नई दिल्ली । नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके जाफराबाद के इंदिरा चौक पर अलग-अलग समुदायों के स्थानीय निवासियों की मदद से नवनिर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण पूरा हुआ. सीलमपुर से आप विधायक चौधरी जुबैर अहमद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. मंदिर के पुजारी ने कहा कि चौधरी जुबैर अहमद ने पूरा सहयोग किया. न्यूज एजेंसी से बातचीत में मंदिर के पुजारी लालमणि शुक्ला ने कहा, मैं बीते 23 सालों से इसमें रहता था. लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी हूं. ये मंदिर एक दम जर्जर हो गया था, टूट गया था. इसे मैं अपने जजमानों द्वारा, मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा, सबसे जहां से जो मिला लाकर किसी तरह से इसको बनवाया. आज मूर्ति स्थापना, हवन-पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया है. आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद के सहयोग पर उन्होंने कहा, विधायक चौधरी जुबैर की तरफ से सारा सहयोग था कि पंडित जी मैं बैठा हूं. आप बनवाइए, कोई हस्तक्षेप करना है तो मैं बैठा हूं.

समाधान शिविर में अधिकारियों की मेहनत का जरूरतमंदों को मिल रहा लाभ : निगम संयुक्त आयुक्त डॉ. संजय

पानीपत।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा प्रदेश के सभी जिलो व उप मण्डलों में आयोजित किए जा रहे जनता समाधान शिविर की इस कड़ी में वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए निगम संयुक्त आयुक्त डॉ. संजय ने कहा कि ये जनता समाधान शिविर निर्बल लोगों के लिए लाभदाई है। इसमें जरूरतमंद को अधिकारियों की मेहनत का लाभ मिल रहा है। इसमें वही लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं जो ज्यादा जरूरतमंद है व जिनकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा था। ऐसे लोगों की मदद करना हमारा सब की बड़ी जिम्मेदारी है। सभी अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का

समाधान तत्काल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का बस एक नजरिया जरूरतमंद लोगों की जिन्दगी को आसान बना सकता है। इस कार्य में हमारे द्वारा लिया गया निर्णय जरूरत मंद लोगों के लिए वरदान है। समाधान शिविर में डीएसपी हेड क्वार्टर सतीश वत्स ने कहा कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय एकजरूरत मंद को बड़ा फायदा पहुंचा सकते है। इसका हमें इलम होना चाहिए। हमें समाधान शिविर में पहुंचने वाली हर समस्या का समाधान करना है। उन्होंने पुलिस विभाग से सम्बन्धित पहुंची अनेकों समस्याओं पर संज्ञान लिया व थानों के एसएचओ को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। समाधान शिविर मे डीडीपीओ राजेश शर्मा ने कहा कि कोई भी समस्या उस वक्त तक बड़ी है जब तक हम उसे दूर करने का निर्णय नहीं लेते। हमें समाधान शिविर में कायदे व हिम्मत को आगे रखकर आम जन की समस्याओं को दूर करना है। विदित रहे कि ज्यादातर समस्याएं क्रीड विभाग से जुड़ी हुई है। जिनका अधिकारियों द्वारा तन्मयता से समाधान किया जा रहा है। समाधान शिविर में पैंशन विभाग, क्रिड विभाग, बिजली विभाग से सम्बन्धित 84 समस्याएं समाधान शिविर में दर्ज हुईं। निगम संयुक्त आयुक्त ने कहा की अधिकारियों के सहयोग से समस्याओं का मौके पर समाधान करने के प्रयास किए गए। प्रार्थी मोहित वासी नारा ने बिजली का खंबा हटाने के लिए प्रशासन से प्रार्थना की उन्होंने खंभे के कारण बढ़ रहे समस्याओं का भी उल्लेख कियाप्रार्थी बदलू राम ने बताया कि धान का मौसम है।

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी मेंराजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फ्रंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया -सक्षम भारत

दिल्ली के आठ स्कूलों को बम से उड़ाने धमकी, 72 घंटे में 10 मामले सामने आए, इसके पीछे कौन?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने से अफरा-तफरी मच गई. पूरे स्कूल परिसरों को तुरंत खाली कराना पड़ा. हालांकि, व्यापक जांच के बाद ये धमकियां अफवाह साबित हुईं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 15 जुलाई को द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल में बम की धमकी भेजने के आरोप में 12 वर्षीय एक छात्र को हिरासत में लिया गया था. इन स्कूल को 24 घंटे से भी कम समय में एक और बम की धमकी मिली. पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि मंगलवार को बम की धमकी वाला ई-मेल भेजने वाले लड़के की पहचान कर ली गई है और उसे हिरासत में ले लिया गया. अंकित सिंह ने एक वीडियो बयान में कहा, ''लड़के की काउंसलिंग की गई और उसे परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया.'' पुलिस के मुताबिक सेंट थॉमस स्कूल के साथ-साथ सात अन्य स्कूलों को भी बुधवार को ई-मेल मिला, जिसमें बम रखने की धमकी दी गई थी. हालांकि, जांच के बाद सभी धमकियां फर्जी पाई गईं. अधिकारियों ने बताया कि वसंत कुंज स्थित वसंत वैली स्कूल, हौज खास स्थित मदर इंटरनेशनल, पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल, पश्चिम विहार और पीतमपुरा स्थित फ्रेंडस स्कूल, लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय और पश्चिम विहार के सेंट थॉमस स्कूल को इस तरह की धमकियां मिली थीं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये ईमेल सुबह 5.26

बजे से 8.12 बजे के बीच प्राप्त हुए. स्कूलों को कुल 10 ईमेल मिले. उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसरों की गहन जांच की गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. यह लगातार तीसरा दिन था, जब दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. हालांकि, सभी धमकियां फर्जी निकलीं. सरदार पटेल विद्यालय के स्कूल अधिकारियों ने अभिभावकों को भेजे गए एक ईमेल में कहा, ''आज सुबह बम की संभावित धमकी मिलने के कारण और पुलिस की सलाह के अनुसार, सरदार पटेल विद्यालय आज बंद रहेगा. बम निरोधक दस्ता परिसर की गहन जांच कर रहा है.'' इन स्कूलों में रात में भी रहने वाले कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते, श्वान दस्ते और साइबर विशेषज्ञों की टीम स्कूलों में पहुंचीं और उन्होंने गहन तलाशी ली. अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राहुल गांधी हमलावर

क्या इलेक्शन चोरी ब्रांच बनकर रह गया है चुनाव आयोग?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की चुनावी चोरी शाखा बन गया है। वहीं, चुनाव आयोग हमेशा से कहता रहा है कि 22 साल बाद हो रहे इस पुनरीक्षण से मतदाता सूची से अपात्र लोगों और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाया जाएगा और कानून के अनुसार मतदान के पात्र लोगों को भी शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग एसआइआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम 'एसआइआर' - पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआइआर ईसी अब भी 'चुनाव आयोग है या पूरी तरह बीजेपी की 'चुनाव चोरी' शाखा बन चुका है? वहीं, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि नागरिकता प्रमाणित करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है तथा विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) शुरू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब आयोग अपने ही तर्कों में फंस गया है और 'मुद्दा भटकाओ योजना' के तहत नेपाल, म्यांमा और बांग्लादेश के लोगों के बिहार में होने की कहानी गढ़ रहा है। कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में संवाददाताओं से कहा, ''यदि 2003 की पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत थी, तो उसके बाद के सभी चुनाव गलत हैं...क्या नरेन्द्र मोदी जी को म्यांमा और नेपाल के लोगों ने वोट दिया...अगर ऐसा है तो फिर बिहार के सभी 40 सांसदों को अयोग्य घोषित करिए और फिर से चुनाव करवाइए।'' कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''क्या मतदाता सूची किसी राजनीतिक दल ने बनाया या निर्वाचन आयोग ने बनाया।

पहलगाम में गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों की हुई पहचान

एलजी मनोज सिन्हा का ऐलान- जल्द ही उन्हें मार गिराएंगे, अच्छी खबर मिलेगी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिरा दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने गांधी स्मृति में 'जम्मू-कश्मीर शांति की ओर' विषय पर व्याख्यान देते हुए जोर देकर कहा कि कश्मीर घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया मिली। हमले को अंजाम देने वालों की पहचान कर ली गई है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब उनका जिंदा रहना मुश्किल है। अच्छी खबरें जरूर आएंगी, लेकिन कोई निश्चित तारीख बताना उचित नहीं होगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले पांच साल में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के शीर्ष आका भी अब जिंदा नहीं रहे और उनका (आतंकियों का) भी यही हश्र होगा। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों एक अखबार को दिये साक्षात्कार में मनोज सिन्हा ने कहा था कि वह पहलगाम हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देर से ही सही, लेकिन आखिरकार स्वीकार कर लिया कि पहलगाम हमले के लिए खुफिया विफलता जिम्मेदार थी। उन्होंने इस आतंकवादी हमले के सिलसिले में जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उमर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 80 दिन बाद ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमने यह (पहले) नहीं कहा, जबकि हम जानते थे कि इतना बड़ा हमला (खुफिया) विफलता के बिना नहीं हो सकता। उमर ने कहा कि अब जब विफलता स्वीकार कर ली गई है, तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा दांव, 125 यूनिट फ्री देने का ऐलान

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। यह घोषणा इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले की गई है। यह राज्य में इस तरह का पहला और चुनावों से पहले की गई रियायतों की श्रृंखला में नवीनतम कदम है। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सीएम ने आगे लिखा कि इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।

पटना के अस्पताल में 30 सेकेंड में गैंगस्टर का मर्डर

पटना। पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार (17 जुलाई, 2025) की सुबह चंदन नाम के एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस शूटआउट का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें अपराधियों की तस्वीरें कैद हुई हैं. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पांच की संख्या में बदमाश बड़े आराम से पारस अस्पताल में घुसते हैं और चंदन जिस वार्ड में रहता है उस तरफ बढ़ते हैं. वार्ड में एक-एक कर सभी पांच बदमाश घुस जाते हैं और गोलीबारी कर हत्या कर देते हैं. वीडियो में सारे बदमाशों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं. यानी पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना आसान होगा. पांच में से चार बदमाशों के सिर पर टोपी है. एक बदमाश जो सबसे आगे है उसने टोपी नहीं पहनी है. हत्या के बाद बड़े आराम से एक-एक कर सभी मौके से फरार हो जाते हैं. वीडियो को

देखकर आपको लगेगा कि यह कोई फिल्म है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हत्या करने वाले बदमाशों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है. वे वार्ड के बाहर दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं एक-एक कर हथियार निकाल लेते हैं. सबसे पहले आगे चलने वाले बदमाश ने हथियार निकाला. उसके बाद उसके साथ जो पीछे में अपराधी थे उन लोगों ने हथियार निकाल लिया.

कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर सरकार पर किया हमला

बिहार कांग्रेस ने वीडियो को शेयर करते हुए एनडीए सरकार पर हमला किया है. एक्स पर लिखा है, बिहार का गुंडा राज. पिछले 17 दिन में 46 मर्डर हुए है. अब राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में बदमाश हथियार लेकर घुसे और गोलियां चलाकर मर्डर कर दिया. ये वीडियो देखिए और समझिए बिहार में अपराधी

वॉर्ड में घुसे 5 बदमाश; गोली मारी और भाग निकले

कितने बेखौफ हैं.

अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं

इस घटना के वीडियो को इंडियन यूथ कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी शेयर किया गया है. लिखा गया है, पटना के पारस अस्पताल में खुलेआम हथियार लेकर घुसे अपराधी.. गोलियों की बौछार में एक और हत्या! बिहार में अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब राजधानी के अस्पताल भी सुरक्षित नहीं हैं.

17 दिन, 46 मर्डर.. यही है सुशासन बाबू का नया बिहार?

कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार का गुंडा राज. पिछले 17 दिन में 46 मर्डर हुए हैं. यह वीडियो राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल का है. 5 हत्यारे बेखौफ हथियार लेकर घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाकर मर्डर कर के निकल लिए. बिहार में ओटीटी से भी ज्यादा खौफनाक सीरीज असल जिंदगी में चल रही है.

मुकेश सहनी बोले- बिहार बना क्राइम कैपिटल

पारस अस्पताल में हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी एनडीए सरकार पर हमला किया है.

सहनी ने एक्स पर लिखा है, बिहार बना क्राइम कैपिटल! पटना की सड़कों से लेकर अस्पतालों तक गोलियां चल रही हैं. जनता दहशत में, लेकिन नीतीश-भाजपा की सरकार बेफिक्र है!

संघ ने मोदी की रिटायरमेंट के दिए संकेत, भाजपा के पास दलित पीएम बनाने का मौका : सिद्धारमैया

बंगलूरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल की उम्र पूरी होने के साथ ही उनके राजनीतिक रिटायरमेंट का संकेत दे दिया है। अब भाजपा के पास यह सुनहरा मौका है कि वह एक दलित को अगला प्रधानमंत्री बनाए। यह बयान उन्होंने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र के उस चैलेंज के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि वह अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके दिखाए। सिद्धारमैया ने कहा, खरगे सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, बल्कि एक सम्मानित और अनुभवी नेता हैं। उनका संघर्ष और समर्पण दशकों पुराना है। उन्होंने कभी भी दलित कार्ड नहीं खेला। कांग्रेस में प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला हमारी पार्टी करती है, भाजपा नहीं। उन्होंने विजयेंद्र को नसीहत दी कि वे कांग्रेस पर टिप्पणी करने की बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दें। उन्होंने आगे कहा अब जब मोहन भागवत ने मोदी को रिटायरमेंट का इशारा दे दिया है, तो भाजपा को चाहिए कि किसी दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाए। अगर आप सच में दलितों की चिंता करते हैं तो गोविंद करजोल या चलवादी नारायणस्वामी जैसे नेताओं के नाम आगे बढ़ाइए - मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा में दलितों और पिछड़ों के लिए जगह केवल दिखावे की होती है। उनका इतिहास और व्यवहार दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। सिद्धारमैया ने विजयेंद्र से पूछा कि अगर वे इतने ही ईमानदार हैं तो खुद कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर किसी दलित नेता को यह पद सौंप दें। सिद्धारमैया ने आगे कहा अगर नाम नहीं सूझ रहा, तो मैं एक नाम सुझाता हूं- गोविंद करजोल। मैं उन्हें जानता हूं, वह एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे।

बाघों ने मचाया आतंक, तीन हमले... महिला की मौत, दो घायल

पीलीभीत। पीलीभीत के न्यूरिया इलाके में दो किसानों की जान लेने वाले बाघों ने फिर आतंक फैला दिया। बृहस्पतिवार सुबह दो घंटे के अंतराल में बाघ ने अलग-अलग जगहों पर दो महिलाओं समेत तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इनमें मंडरिया गांव निवासी 50 वर्षीय तृष्णा की मौत हो गई। वह सुबह-सुबह खेत पर गई थी, तभी बाघ उन्हें दबोच ले गया। उनका शव खेत से बरामद हुआ। इससे 15 मिनट पहले मंडरिया के ही किशोर नीलेश पर बाघ ने हमला किया। नीलेश करीब 10

मिनट तक बाघ से लड़ता रहा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ उसे छोड़कर भागा। मंडरिया से पहले सहजनिया और अनवरगंज गांवों में दूसरा बाघ देखा गया है। इस बाघ ने सुबह करीब छह बजे सहजनिया गांव निवासी मीना (50 वर्ष) पर हमला कर दिया। वह खेत पर जा रही थी, तभी गन्ने के खेत से निकले बाघ ने उन्हें दबोच लिया और 20 मीटर तक खींच ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर छोड़कर भाग गया। हमले से मीना गंभीर घायल हो गईं। उनकी पीठ में गहरा घाव हुआ है। घायल अवस्था में उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मंडरिया गांव में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना मिलते ही डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी अभिषेक यादव फोर्स के साथ गांव पहुंच गए। वन विभाग की टीमें भी गांव में मौजूद हैं। इलाके में बाघों की तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन बाघ लगातार चकमा दे रहा है। सहजनिया और अनवरगंज के खेतों और सड़क पर घूमते बाघ का ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया है।

ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में दो बाघ हैं। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यशैली को लेकर रोष है।

ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि बाघ की लगातार बढ़ रही चहलकदमी को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति की मौत की सजा को बिना किसी छूट के उम्रकैद में बदल दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिर्फ अपराध की निर्दयता पर टिप्पणी की और दोषी को मौत की सजा सुना दी। 16 जुलाई को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों ने

निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी अन्य परिस्थिति पर विचार नहीं किया और मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ माना। लेकिन हमारे विचार से इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। पीठ ने प्रोबेशन अधिकारी, जेल प्रशासन और दोषी की मानसिक रिपोर्ट की समीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि इनसे पता चलता है कि दोषी के परिवार की हालत बेहद खराब है और वे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। साथ ही दोषी व्यक्ति 12 साल की उम्र से मजदूरी कर रहा है और कभी भी स्कूल नहीं गया। पीठ ने कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए और दुर्लभतम से दुर्लभ कैटेगरी की सीमा को देखते हुए हमें लगता है कि दोषी को बिना छूट के उम्रकैद की सजा देना ज्यादा ठीक है न कि मौत की सजा देना। दोषी व्यक्ति ने जनवरी 2020 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुलाई 2018 में मिठाई के बहाने से बुलाकर दोषी ने नाबालिग से अपनी झोपड़ी में दुष्कर्म किया और फिर सबूत मिटाने के मकसद से पीड़िता की हत्या कर दी। दोषी की झोपड़ी से पीड़िता के शव की बरामदगी, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत और डीएनए जांच के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

पीएम मोदी का बिहार और बंगाल दौरा

*आज दुर्गापुर में रैली को संबोधित करेंगे; करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिहार के मोतिहारी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे दुर्गापुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा कुछ प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगभग सुबह 11:30 बजे बिहार दौरा शुरू होगा। वह बिहार से कई नई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे, जिसमें लागत 580 करोड़ रुपये से अधिक की दरभंगा-समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना भी शामिल है। इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी और देरी कम होगी। प्रधानमंत्री कई नई रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। लगभग 4,080 करोड़ रुपये की दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का भी शिलान्यास होगा। इससे अधिक यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा, और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार के विभिन्न स्थानों से लखनऊ और दिल्ली के लिए चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम राष्ट्रीय राजमार्ग-319 के आरा बाईपास के 4-लेन निर्माण की आधारशिला रखेंगे, जो आरा-मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग-319 और पटना-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग-922 को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग-319 के परारिया से मोहनिया तक के 4-लेन खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 820 करोड़ रुपये से अधिक है। यह खंड आरा शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग-02 से जोड़ता है।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-333सी के सारवां से चकाई तक पक्की सड़क के साथ दो लेन का निर्माण शामिल है, जो माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाएगा और बिहार और झारखंड के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और पटना में ईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे। बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत स्वीकृत मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बंगाल दौरे पर दुर्गापुर में भाजपा की एक रैली को संबोधित करने और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं।

सीरीज का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की चाबियां सौंपी जाएंगी, जबकि 40 हजार लाभार्थियों के लिए 160 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी।

बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बांकुरा, पुरुलिया, दुर्गापुर और बर्धमान जिलों समेत पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों को भी तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीएलसी) सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दुर्गापुर से कोलकाता तक (132 किमी) की नेचुरल गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (पीएमयूजी) परियोजना के तहत जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन का हिस्सा है। पीएम मोदी दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की 1,457 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली-फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में 390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन (36 किलोमीटर) के दोहरीकरण कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री पश्चिम बर्धमान जिले के तोपसी और पंडाबेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत निर्मित 380 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले दो सड़क ऊपरी पुलों (आरओबी) का उद्घाटन करेंगे।